नदी संरक्षण सत्याग्रह

2008

जलबिरादरी

34/46, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर, (राज.)

फोन/फैक्स : 0141-2393178

Email-watermantbs@yahoo.com

नदी की समझ कैसे बनाएं ?

जलबिरादरी के सभी मित्र नदियों के किनारों पर कोन कैसे कब्जे कर रहा है? पहचान करें, पूछें, क्यों ऐसा कर रहे हैं?

नगर पालिका और पंचायत या उद्योग कोई परिवार नदी में सीधा मैला पानी क्यों डाल रहा है? पूछे। रोकने को कहें। मैले की मैली कोशिश रोकें।

नदी पर बनता बड़ा बांध या टनल, नदी को पाइप में बदलने से रोकना चाहिए। नदी किनारे विकास के नाम पर होते विनाश को रोकें।

भारत की मरती नदियों को रियल स्टेट के अतिक्रमण, खेती और जीवन पद्धति में बदलाव के शोषण, उद्योगों और नगरों के प्रदूषण से बचने हेतु राज–समाज को अपनी भूमिका समझना तत्काल जरूरी है । आज ही हम सब अपनी जीवन पद्धति में कम पानी का उपयोग, प्रदूषित पानी, तालाब, नालों के द्वारा नदी में जाने से रोकें। नदियों को सदानीरा बनाए रखने हेतु पहाड़ों और धरती में हरियाली लाएं ।

नालों को प्राकृतिक रूप में जल शोधन करके नदी में डालें। किसी भी पंचायत और नगर पालिका को गन्दा पानी नदी में डालने का हक नहीं है। इसका अहसास कराना जरूरी है। शुद्ध जल नदी में डालने का आभास कराने की जरूरत वर्ष 2008 में राज–समाज को होना चाहिए।

राज–समाज को नदियों की शुद्धता और सदानीरा बनाने की जिम्मेदारी का अहसास कराना तथा धरती और पहाड़ों की हरियाली का भान कराके मरती नदियों को पुनर्जीवन दान देने की प्रतिबद्धता प्रकट करना है।

हमारी नदियों के संरक्षण सत्याग्रह वर्ष 2008 मनाने हेतु हम 28 दिसम्बर को अरवरी नदी की संसद देव का देवरा गांव में आयोजित करके, उसी में देशभर की नदियों को शुद्ध और सदानीरा बनाने हेतु सभी राज्य

सरकारों तथा भारत सरकार को अपनी नदियों के दायित्व को समझाने की शुरुआत अरवरी संसद के नदी संदेश द्वारा करायेंगे।

अरवरी संसद तो अरवरी नदी का समाज है। इस समाज ने अपनी नदी का शोषण–प्रदूषण रोक कर मरी नदी को पुनर्जीवित बनाया। सरकार तो नदियों पर कब्जा कर रही है। इनमें प्रदूषण बढ़ा रही है। इनका शोषण कर रही है। एक तरफ बड़े–बड़े बांध बना रही है। कहीं टनल बना रही है। कहीं पानी लूट कर मेट्रो–शहरों को सैकड़ों कि.मी. पाइप में कैद करके दे रही है। गांव बेपानी बन रहे हैं। इस प्रकार गांव–शहर में जल झगड़े बढ़ा रही है।

अरवरी संसद ने नदी के कब्जे, पानी की लूट, प्रदूषण सब कुछ रोका है। इसलिए इस संसद को प्रकृति–प्रदत्त नैतिक हक से सरकारों पर सत्याग्रह का दबाव डालना जरूरी है। सरकारें अरवरी संसद के नैतिक दबाव से कुछ सीख लेकर नदियों को संरक्षण प्रदान करेंगी। इस दिशा में राज–समाज की नदी चेतना जगाने हेतु 1 जनवरी से जहां–तहां समाज तैयार होगा, वह अपनी नदियों को बचाने की यात्राएं शुरू करेगा।

जलबिरादरी ने उत्तर एवं दक्षिण की नदियों में सत्याग्रह यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया है। पूरे भारत में नदी संरक्षण साक्षरता अभियान की योजना दिसम्बर 16–17 को जयपुर में बैठक कर तैयार की है।

यमुना सत्याग्रह एक अगस्त 2007 से जारी है। गंगा सत्याग्रह भी 2008 में शुरू होगा। छोटी–छोटी नदियों को भी शुद्ध एवं सदानीरा बनाने हेतु हमारी सभी राज्यों की जल बिरादरी काम शुरू करेगी।

जलबिरादरी के अध्यक्ष (श्री राजेन्द्र सिंह) दिसम्बर 22–23 को मुम्बई–पूना में महाराष्ट्र के साथियों से तैयारी बैठक के लिए गये हैं। दिसम्बर 26–27 को दिल्ली–उत्तर प्रदेश में शुरू करायेंगे। 28 दिसम्बर को केरल कोचीन, दिसम्बर 29–30 को चैन्नई में तैयारी प्रशिक्षण देंगे। दिसम्बर 31 को दक्षिण नदी सम्मेलन होगा। 1 जनवरी से 'नदी बचाओ

सत्याग्रह' यात्राएं शुरू होंगी। सभी जलबिरादरी साथियों से प्रार्थना है कि नदियों को बचाने हेतु अपनी नदियों पर सत्याग्रह शुरू करें।

नदी संरक्षण सत्याग्रह 2008

भारत की शुद्ध–सदानीरा नदियां अभी तक प्रदूषण और शोषण की मार झेल रही हैं। अब नई बड़ी मार रियल स्टेट ने विविध रूपों में कब्जे शुरू करने से की है। कहीं मन्दिर तो कहीं गुरुद्वारे, मस्जिद बनाकर धर्म संस्कृति की दुहाई देकर कब्जे हो रहे हैं, तो कहीं खेलगांव, मैट्रो डिपो, राष्ट्रहित बताकर मॉल–होटल, हवाई अड्डे, रिवर व्यू विकास के नाम पर नदियों का विनाश और कब्जे देशभर में सभी नदियों पर प्रारम्भ हो गए हैं। देश का कोई शहर ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि हमने नदियों को बचाया है। उन्हें आज शुद्ध–सदानीरा और स्वच्छता से बहने की स्वतंत्रता है। हमारे गांव आज भी कह सकते हैं कि 'हमने मरी–सूखी अरवरी नदी को शुद्ध–सदानीरा बनाकर पुनर्जीवित किया है।'

भारत में भूमि के भाव बढ़े तो नदियों पर संकट के बादल छाये हैं। इस बढ़ते संकट को रोकने हेतु देशभर से आवाज उठी है। क्या कोई सुनने वाला है ? सरकार जवाब दे रही है 5 प्रतिशत नदियों को बेचकर 95 प्रतिशत नदियों का प्रबन्ध करेंगे। शेष सब को बचाने–बनाने का काम करेंगे या नहीं? बेचने वाला बनाता नहीं। जोड़ता और मिलाता नहीं है। वह तो केवल बिखेरता और बिगाड़ता है।

आज नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह काम प्रकृति स्वयं ही करती है। जहां जिस नदी को जुड़ना है वह स्वयं ही जुड़ जाती है। जैसे गंगा–यमुना एक ही पर्वत हिमालय से निकलती हैं। इलाहाबाद में फिर मिलती हैं। नदियों को कोई व्यक्ति, कम्पनी नहीं जोड़े, बल्कि यह कार्य स्वयं प्रकृति ही करेगी। नदियों की शुद्धता, धरती की हरियाली और उद्योगों की शुद्ध जल निकासी से नदियों से कब्जे हटाकर नदियों को आजाद रख सकते हैं। नदियों को बेचें नहीं। बचायें। जुट–मिल कर साथ चलेंगे तो ही

नदियां बचेंगी । नदियों से समाज जुड़े। समाज का मन–मानस नदियों से जुड़ेगा, तभी नदियां बचेंगी। इसी हेतु नदी सत्याग्रह की जरूरत है।

नदियों में स्थाई विनाश का काम यमुना नदी में अक्षरधाम मंदिर के निर्माण से सन् 2000 में आरम्भ हुआ था। अब इसी काम को दुबई की एक कम्पनी द्वारा कॉमनवैल्थ खेल संघ, भारत सरकार की मौन स्वीकृति से करा रही है। भारत सरकार के वैज्ञानिक, राजनेता, अधिकारी, व्यापारी, पुजारी सब जानते हैं। नदियों के खत्म होने से समाज बेपानी हो जाएगा। ये सब अपने निजी स्वार्थ हेतु नदियों को खत्म कर रहे हैं।

समाज नदियों के बारे में मौन है। मरती, बेपानी बनती नदियों को देख रहे हैं। हम विद्यार्थी, शिक्षक, किसान मौन हैं, क्या नदियों को नष्ट करने वाले काम में शामिल हैं? फिर मौन क्यों? नदियों को बचाने हेतु खड़े क्यों नहीं हुए? जहां कहीं नदियों की आवाज है। वहां हम अपनी आवाज इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं?

उपराज्यपाल दिल्ली ने अपने आश्वासन में 12 सितम्बर को कहा 'यमुना नदी में नये निर्माण कार्य नहीं होंगे' मुख्यमंत्री भी यमुना नदी को प्यार करती हैं, तभी तो नदी किनारे बसे गरीबों को उजाड़कर, नये सरकारी कब्जे और बड़ा विशाल मन्दिर बनवाया।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नदियों की कीमत जानती हैं। हम और हमारी सरकारें क्या पानी की कीमत नहीं जानती हैं ? इसीलिए नदियों के पानी के भण्डार खादर को विदेशी कम्पनियों को निर्माण हेतु बेचने के ठेके दे रही हैं। यमुना सत्याग्रह के 150 दिन पूरे होने पर स्थिति वैसी ही बनी हुई है। सरकार नदियों की लूट और प्रदूषण क्यों नहीं रोक रही है ?

नदी को दिल्ली में नष्ट होने का 'सत्य' हम जानते हैं। इसे बचाने हेतु आग्रह कर रहे हैं। यही हमारा सत्याग्रह है। अब पूरी नदियों का सत्य हमें जानना है। इसके लिए सरकारी और गैर–सरकारी वैज्ञानिकों के एक दल के साथ इस सत्य को जानने हेतु 'नदी शोध' यात्रा शुरू करनी है।

नदी सत्याग्रह तैयारी कार्यक्रम –

1. देश की नदियों से समाज को जोड़ने के तरीके खोजने हैं।
2. विकास के नाम पर नदियों के हो रहे विनाश को रोकने का मन–मानस तैयार करने की संभावना तलाशना।
3. राजनेताओं, अधिकारियों तथा सरकारी वैज्ञानिकों का मन–मानस प्रकृतिमय बनाने की विधियों पर यात्रा में चर्चा करना।
4. नदियों को शुद्ध सदानीरा बनाने हेतु राज–समाज के मन–मानस को अनुकूल बनाना।
5. नदियों की भू–सांस्कृतिक संरचनाओं, जैविक विविधता का सम्मान करते हुए, नदी की अपनी स्वतन्त्रता व प्राकृतिक सत्ता को सरकारी मान्यता दिलाने की जरूरत का अहसास कराना है।
6. शिक्षार्थियों–शोधार्थियों को प्रकृति से सीखने की दृष्टि बनाना, हमारे साझे भविष्य का विनाश रोककर ये समृद्धि का रास्ता अपनाएं।

नदी संरक्षण के नाम पर सरकार सब नदियों को बेचकर नदियों का चेहरा सुधारने की बात कर रही है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना है। यह कार्य सरकार सबसे पहले यमुना में ही शुरू करने वाली है। इसलिए नदियों के विनाश कार्य को रोकने की सबसे पहले यमुना में ही जरूरत है। इसलिए तत्काल यमुना बचाने हेतु सभी 'हम मिलें–जुटें और यमुना बचाने चलें।'

सत्याग्रही दल

17 से 21 शोधार्थियों की टोली में जल, नदी, पर्यावरण, भूविज्ञान, समाज कार्य की समझ रखने वाले तथा संरक्षण के साथ–साथ प्रकृति प्रेमी, विकास प्रेमी और किसान, मजदूर, मल्लाह भी रहेंगे। विकास का विनाश रोकने वाले तथा संरक्षण के साथ विकास कार्यों में प्रकृति को पुनर्जीवित बनाकर, उजड़े समाज की लाचारी, बेकारी दूर करके पुनर्वास और समृद्धि कायम करने वाले समाजकर्मी भी दल में रहेंगे। नदी से मां जैसा व्यवहार करने वाले भाई–बहिन जल को मानव

अधिकार और जल को जीवन का आधार मानने वाले शिक्षक भी शामिल रहेंगे। हम अपने देश के सभी नदी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को भी इस यात्रा से जुड़ने की प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार के साथ नदी संरक्षण की स्वराज संवाद चलाने की गुहार है। इससे धरती की हरियाली, नदियों की शुद्धता और सदानीरा बनाने की चेतना जगानी है। इस साझे कार्य में हम जब जुटें। जो इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, वे सब विद्यालय–महाविद्यालय हमें लिखें।

नदी सत्याग्रही की नजर में नदियों को बचाने में राज–समाज की साझी और अलग–अलग भूमिकायें

नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने में गरीब–अमीर, हिन्दू–मुस्लिम, सिक्ख–ईसाई आदि सब की साझी और समान भूमिका है। इसी तरह राज–समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राज और राज्य संचालक वर्ग की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि नदियों को गंदी बनाकर मारने वाला काम राज्य ने ही करवाया। इस गलत काम को रुकवाने हेतु प्रथम जिम्मेदारी भी राज्य की है।

'क' नदी मुक्ति हेतु राज की भूमिका

1. नदी भूमि का उपयोग नहीं बदलना।
2. नदी पर कब्जा करने वालों को सजा देना।
3. नदियों को मैली बनाने वालों को दण्डित करना।
4. नदियों पर सीमेन्ट–कंकरीट का जंगल बनाने वालों को पहले राज उनके कब्जे हटाकर दण्डित करे व साथ ही राज उन नदियों को पुनः पवित्र व शुद्ध बनाने हेतु कार्य करे ।
5. ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे कोई गांव–शहर, व्यक्ति या उद्योग नदियों को मैली नहीं कर सके और उसे सख्ती से लागू करवाना। नदी पवित्रता को बनाने का काम सब मिलकर करें।
6. नदी भूजल रिवर बैड में कोई भी किसी तरह का निर्माण नहीं हो सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जाये। खादर के सभी निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोकना।

7. राजस्थान की अरवरी नदी से प्रेरणा लेकर, नदी पुनर्जीवित करने हेतु प्राकृतिक जल धाराओं, जल, जंगल, जमीन और जीव संरक्षण किया जाये।
8. नदियों के ग्रीन बेल्ट को ग्रीन बेल्ट ही बनाकर रखें।
9. अधिकतर नदियों को चम्बल की तरह संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाये। इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होवे।
10. नदियों से सभी प्रकार के कब्जों को हटवायें।

'ख' समाज की भूमिका–समाज में विद्यार्थी और शिक्षक ही अच्छे कार्यों के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। नदियों को बचाने का काम पवित्र है। इसमें भी सबसे पहले ये ही आगे आयेंगे।

'अ' शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका

1. विद्यार्थी, शिक्षक नदियों में नये कब्जों पर निगरानी रखें। अपने–अपने विद्यालय की साझी जिम्मेदारी विद्यालयवार बांटकर नये कब्जे रोकें।
2. गंदे नाले और मल–मूत्र–कचरा नदियों में नहीं जाए, इस हेतु जो भी सरकारी कोशिश हुई है या होने वाली है उसकी निगरानी और शुद्धि रखना। नदियों के नाम पर हुए अन्याय–अत्याचार को रोकें। नदियों से भ्रष्टाचार को मिटाएं।
3. नदियों के किनारे वृक्षारोपण करें। प्रत्येक विद्यार्थी एक पेड़ नदी के लिए लगाये और उसको बचाए।

'आ' वैज्ञानिक भूमिका

1. नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने वाला सत्य प्रचारित–प्रसारित करें।
2. नदियां सबको पूरा पानी पिला सकती हैं। इस सत्य को आग्रह–पूर्वक सरकार से मनवायें। सरकार रिवर बैड में निर्माण नहीं

करे । सरकार नदी का लैण्डन्यूज नहीं बदले, इस पर निगरानी रखें। नदियों की मुक्ति हेतु सभी तरह के सत्य का शोध करके समाज को बताएं ।

'इ' किसानों की भूमिका

1. नदी क्षेत्र में सजीव खेती, खाद्यान्न, सब्जियां उपजायें, पेड़–पौधे भी लगाएं ।
2. नदियों की जमीन को प्रदूषित नहीं होने दें तथा इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए सहयोग करें।

'ई' बिल्डर्स की भूमिका

नदियों को नष्ट करने वाली बुरी नजर बिल्डरों की है। देश की सब नदियों पर इन्होंने बुरी नजर लगाई है। सबसे अच्छा बिल्डर अपने लाभ से पहले सबका शुभ चाहता है, वही बिल्डर सुखी और शान्तिमय समृद्धि वाले भवन निर्माण करता है। आज भ्रष्टाचार के कारण बिल्डर की दृष्टि बिगड़ गई है। बिल्डर सबसे पहले अपनी दृष्टि ठीक करें, शुभ के साथ ही लाभ कमाने वाला संस्कार बनायें।

1. बिल्डर नदी को 'मां' की तरह देखें।
2. रेत में महल बनाने का सपना छोड़ें।
3. नदी की सीमा में बिल्डर अपना प्रवेश वर्जित मानें।
4. नदी सबके सुख के लिए है। बिल्डर के लाभ के लिए नहीं है। सब का साझा शुभ ही नदियों से पूरा होता और टिकता है।
5. बिल्डर नदी दृष्य को अपने लिए नहीं पूरे देश और दुनिया के लिए साझा मानकर छोड़ दे ।
6. गरीबों को नदी की रेती में खेलने दें, नदी गरीबों की भी उतनी ही है जितनी बिल्डरों की है । बिल्डर संख्या में कम हैं, गरीब ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा गरीबों की है । सबको

समान हक है। सब ही नदी से बराबर लेंगे तो सबका दायित्व है कि नदियों का ध्यान रखें तब ही नदियां बचेंगी।

7. नदी और जल की जंग में, बिल्डर भी रहें, सब के संग में।

'उ' उद्योगपतियों की भूमिका

नदियों को मां से मैहरी बनाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उद्योगपतियों की है। इन्होंने ही उद्योग का मैला नदियों में डालकर मैली बनाया है। इन्हें अब अपनी इस बुरी नजर को ठीक करके नदी को मैली होने से रोकना है। कोई भी उद्योग अपना मैला नदियों में नहीं जाने दे।

उद्योगपति स्वयं सब के साझे शुभ का ख्याल करें। केवल लाभ नहीं देखें। इस शताब्दी में समाज ने नदियों को शोषित और प्रदूषित बना दिया है। नदियां इन्हीं की शिकार हैं। इनके भ्रष्टाचार और विचार ने नदियों की शुद्धि के संयंत्रों को नकारा बना दिया है। राजनेताओं को मैली राजनीति उद्योगपतियों ने सिखाई है।

1. मैले की मैली कमाई बंद करें।
2. धरती–प्रकृति से जितना लेते हैं, उतना ही उसी रूप में धरती और प्रकृति को लौटाएं।
3. प्रदूषक भुगतान करने वाला सिद्धान्त अब तक किये प्रदूषण से मुक्ति हेतु अपनाएं।
4. आगे प्रदूषण करें ही नहीं, का सिद्धान्त स्थापित करें। प्रकृति साझी है। इसका शोषण–प्रदूषण करने की छूट उद्योगपतियों को नहीं है। उद्योगपति जितना और जैसा उद्योग के लिए लेवें वैसा ही उतना ही ठीक करके प्रकृति को वापस लौटा दें। प्रकृति का विनाश किसी भी कीमत पर करने की छूट उद्योगपति को नहीं है। इस सिद्धान्त को मानें और अपनायें।

5. नदियां उद्योगपतियों की नहीं हैं। सबकी हैं। सब खड़े होकर उद्योगपति का उद्योग बन्द करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर ही उद्योगपति काम करें।

6. अब तक नदियों के साथ किये बुरे कर्मों का पाप धोने हेतु नदियों की शुद्धि में मदद करें। आगे नदियों को दूषित ना करें।

'ऊ' राजनेताओं की भूमिका

नदियों का प्रदूषण और शोषण का सारा दोष राजनेताओं के खाते में लिखा है। क्योंकि साझी सम्पदा, साझे भविष्य, साझे काम व राष्ट्र और समाज को ठीक रास्ते पर चलाने का दायित्व हम अपने मत से इन्हें सौंपते हैं। हमारे मत का उपयोग करके सत्ता का सारा लाभ ये अपनी निजी सुख पाने में लगाते हैं। साझी विरासत पर इनका ध्यान नहीं रहता।

साझे जीवन और साझे मान–सम्मान सब को ही ये भूल जाते हैं। इसी कारण साझी सम्पदा नष्ट होती जाती है। इनकी निजी सम्पदा बढ़ती जाती है। नदियां सभी की हैं और इस पर सभी का हक है। इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह दूषित होकर मर रही हैं। नदियों को मारने का दोष सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं पर है। ये सत्ता के गलियारों में बहकर ही दूषित हुई हैं। इसे बचाने का काम भी इन्हीं का है। ये ही इसमें पानी पीएं और इसमें स्नान करें। तो ही इनके बुरे कर्मों की इन्हें याद आयेगी। नदियों में स्नान करके अपनी भूलों को स्मरण करके क्षमा मांगकर समाज को नदियों के साथ जोड़ने की अपील राजनेता करें।

राजनेताओं के बुरे कर्मों का पाप उक्त करने से धुल जायेगा। फिर समाज नदियों के साथ जुड़कर नदियों को शुद्ध बनाने में जुटेगा। राजनेता पहल करें। दिखाने के लिए नहीं नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने हेतु काम करें। गरीबों को नदियों के किनारे जाने का हक दिलाने वालों, शुद्ध–सदानीरा बनाने हेतु काम करने वालों को ही वोट मिलेगा, ऐसा वातावरण निर्माण करें।

मन्दिर, अमीर और गरीब के एक जैसे ही होते हैं। गरीबों के सैकड़ों मन्दिर तोड़कर अमीरों के एक मन्दिर के नाम पर लोगों को लूटने वाला मॉल बनवा दिया, ऐसा काम करने वाले को मत देंगे? ऐसा करने वालों को अब वोट नहीं लेना चाहिए। अब तो वोट उसे देंगे जो नदियों को प्रदूषण, शोषण और कब्जों से मुक्ति दिलायेगा। वही दिल्ली का राजनेता बनेगा। दिल्ली का भू–जल भरने वाली शुद्ध–सदानीरा नदी चाहिए जो इस दिशा में काम करेगा। वही राष्ट्रीय नेता बनेगा।

'अं.' सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं की भूमिका

1. समाज का मन–मानस नदियों से जोड़ने के तरीके खोजकर 'समाज को नदियों से जोड़ना है।'
2. नदियों के कब्जाधारियों, भ्रष्टाचारियों की खोज करना। इन्हें रोकने हेतु तैयारी करना। समाज को इस दिशा में संगठित करना।
3. डरी हुई जनता के अन्दर आत्मविश्वास जगाना।
4. **'जल की जंग में, हम सब संग में'**, नदियों की रण में, हम सब जुड़कर–मिलकर बनाने–बैठाने हेतु लगना ही पहला काम बनना चाहिए।
5. सभी नदियों को बचाना और स्वतंत्र शुद्ध–सदानीरा बनाना।
6. नदियों के साथ हुए अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार करने हेतु नदियों को अविरल, स्वतंत्र, शुद्ध–सदानीरा बनाने का सत्याग्रह करना भी स्वैच्छिक संस्थाओं और संगठनों की ही जिम्मेदारी है।
7. नदियों के साथ होने वाले सभी गलत कामों को रोकना है। नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने वाले रचनात्मक काम करना है। इस हेतु नदियों की चेतना यात्रा करके 'नदी बचाओ संवाद' चलाकर, नदी संसद का निर्माण करना है।
8. नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाये रखने के लिए नौसूत्रीय काम करने की जरूरत है।

नदियों की जनोन्मुखी, जलशुद्धि व जल प्रवाहित जल उपयोग करने की विकेन्द्रित व्यवस्था होगी। इसी से नदियों के दोषी को दण्डित करना। संरक्षण करने वालों को सुरक्षा व सम्मान प्रदान करने का काम नदी संसद करेगी। नदियों के प्रति समाज अपनी जिम्मेदारी समझे और आज ही नदियों को शुद्ध–सदानीरा बनाने तथा कब्जों से मुक्ति दिलाने में जुटे।

'अ:' राजनेता, मीडिया, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान व सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलें – 'नदी संरक्षण सम्मेलन' आयोजित करें।

'नदी संरक्षण सम्मेलन'

नदियों के लिए हुई यात्रा के अन्तिम दिन नदी संगम स्थल पर मिलें। मिलकर नदियों को बचाने की प्रक्रिया तय करें। नदियों के संरक्षण, सरकारी कामों की विवेचना और मूल्यांकन करके भावी कार्ययोजना बनायें।

यमुना सत्याग्रह अन्याय का प्रतिकार एवं नदियों के सत्कर्म को साकार बनाने हेतु जैसा चल रहा है, वैसा ही नदियों के भविष्य को सुधारने हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए शिविर–सम्मेलन आयोजित करना जरूरी है। नदियों के सभी काम जन संचालित करने वास्ते नदी संसद बनेगी। नदी संसद कैसे गठित करें, नदी गठन प्रक्रिया तय करने का तंत्र बनायेंगे। बिना चुनाव किये सर्वसम्मति से इसका गठन होगा। मतदाता की योग्यता उसके नदियों हेतु किये गये कामों से निर्धारित की जायेगी। नि:स्वार्थ भाव से नदी सेवा करने वाला ही नदी सांसद बनेगा। ये नदी सांसद नदी बचाने हेतु जरूरी समझें तो अपनी नदियों को बचाने का सत्याग्रह भी शुरू करें।

अरवरी संसद

भीकमपुरा–किशोरी, वाया–थानागाजी

जिला–अलवर (राजस्थान)

नदी हेतु लोकादेश 2008

अरवरी नदी को हमने पुन: जीवित किया। हमने उजड़े सूखे कुओं को पुन: पानीदार बनाया, हरा–भरा बनाया। गांवों की लाचारी, बेकारी, बीमारी से विस्थापित हम अपने पसीने से पुन: पानीदार बने, शहरों से उजड़ कर गांव में बसे हैं। अपनी पुन: जीवित नदी का गंगा संस्कार करके, नदी तीर्थ से अध्यात्म ज्ञान को जीवित करके, हमने नदियों की पवित्रता और धरती की हरियाली बढ़ाई। शोषण–प्रदूषण, अतिक्रमण से नदी को आजादी प्रदान की है।

जैसा हमने अरवरी नदी के साथ किया है, वैसा ही सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार को अपनी सभी नदियों के साथ करना चाहिए। नदी से कब्जे हटाने, प्रदूषण रोकने, जल शोषण बन्द करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके राज्य में अनेकों छोटी व बड़ी नदियां हैं। इन सभी नदियों को जीवनदान देने के लिए आपके जल संसाधन विभाग को ये जिम्मेदारी दें कि वे समाज को साथ लेकर नदियों को सदानीरा बनाएं। इस कार्य में धन से ज्यादा लोगों की भावना महत्वपूर्ण है।

यह केवल भावना का ही सवाल नहीं है बल्कि आपके राज्य की जर–जल–जमीन व जन जीविका का सवाल है। इस हेतु तत्काल नदियों के लिए निम्नलिखित कार्य करवाने चाहिए–

1. नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से लेकर उद्गम –संगम तथा अन्त तक मिट्टी का कटाव रोकने के लिए घास व वृक्षारोपण का कार्य करवाना चाहिये, जिससे नदियों का कटाव रुकेगा।

2. नदियों के कब्जे रोकने के लिए नदी के दोनों किनारों को सुरक्षित–संरक्षित घोषित करना चाहिए जिससे उसमें प्रदूषण, शोषण व अतिक्रमण रुके।

3. नदियों में ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को नदी किनारे मैला डालने का हक नहीं दिया जाये। ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं को मैला ढोने वाले नालों को प्राकृतिक जल संशोधन करके ही नदी में डाला जाए। मशीनी जल संशोधन देश भर में कारगर साबित नहीं हुआ है। अत: स्थानीय परिस्थिति और क्षमता को देख कर स्थायी समाधान होना चाहिए।

4. नदियों के जलभराव क्षेत्र में सीमेन्ट–कंकरीट या अन्य निर्माण नहीं होना चाहिए।

5. नदियों के किनारे नदियों की शुद्धता व पवित्रता बनाये रखने वाले घाट व मन्दिरों जैसे धार्मिक स्थानों को ही स्वीकृति देनी चाहिए। नदी गन्दी करने वाली सभी धार्मिक क्रियाओं को बन्द किया जाए।

6. नदी के सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु से दोनों किनारों पर कम से कम 100 मीटर क्षेत्र में पीपल, बरगद, कदम, गूलर व आंवला जैसे स्थानीय जैव विविधता का सम्मान करने वाले वृक्षों का जायजा व संरक्षण करना चाहिए।

7. नदियों की ऊपरी, मध्य व सबसे नीचे छोरों में जल उपलब्धता के अनुसार फसलों के चक्र सरकारों को निर्धारित करना चाहिए।

8. राज और समाज को मिलकर अरवरी नदी की तरह नदी घाटी संगठन बनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।

9. नदियों की जैव विविधता के संरक्षण व सुरक्षा हेतु राज–समाज को मिलकर नियम बनाना चाहिए।